इस काम के लिये पूर्ण सन्यावह (टोटल मोबिलिज़ेशन) किया तो मुझे पूर्ण आशा है कि हम देश के अन्दर ही काफी रुपया प्राप्त कर लेंगे ।

इसके साथ ही साथ हमारे देश में जो बड़े ज़मीदार और राजा महाराजा है उनके पास अब भी काफी रुपया पड़ा है । बहुत सा ज़ेवर उनका छिपा पड़ा हुआ है, उनके नुमाइन्दे यहां पर बैठे हुये है, फारेन इंवेस्टमेंट को कंफिसकेट कर लेना चाहिये । उद्योगपतियों के जो कल कारखाने है उन्हें सरकार नेशनलाइज़ कर ले और जो उचित मुआवजा है वह दे दे । देश में इस समय सरकारी कर्मचारियों की कमी है । जो राष्ट्रीयकरण द्वारा कल कारखानों को चला सकें इसलिये इन कल कारखानों को सरकार अपने कब्जे में जब कर लेगी तो इन मालदारो और उद्योगपतियों को ही उन कारखानों के जनरल मैनेजर के रूप में रख सकती है और दो चार हजार रुपया तनख्वाह भी दे सकती है । इसी तरह से योजना को पूरा करने के लिये, देश की भलाई के लिये हमें जितनी भी दिक्कतों का सामना करना पडे, सब को, चाहे वह किसान हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, गरीब हो, अमीर हो, टोटल मोबिलिजेशन करके, समान रूप से सामना करना चाहिये ताकि हमारी द्वितीय योजना पूरी हो सके । लेकिन मै समझता हूं कि जिस रूप में हमारा यह काम अभी चल रहा है उससे हमारी योजना पूरी नही हो सकती है । इसमें कमी जो है वह जनता के सहयोग की कमी है । बगैर जनता को साथ लिये हुये हम कामयाब नहीं हो सकते है । जनता को साथ लेना ही नहीं है, उसमें उत्साह भी पैदा करना है । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव की तहेदिल से ताईद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे प्लानिंग मिनिस्टर महोदय इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार करेंगे ।

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT (EXCLUDING RAILWAYS) IN THE YEAR 1957-58

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): Mr. Deputy Chairman, I beg to lay on the Table a statement showing the Supplementary Demands for Grants for Expenditure of the Central Government (excluding Railways) in the year 1957-58. [Placed in Library. *See* No. LT-425/57.]

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

THE COAL BEARING AREAS (ACQUISITION AND DEVELOPMENT) AMENDMENT BILL, 1957

SECRETARY: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary of the Lok Sabha:—

"In accordance with the provisions of Rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith a copy of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Amendment Bill, 1957, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 5th December, 1957."

I lay the Bill on the Table.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2.30 P.M.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at half-past two of the clock, THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. B. JOSHI) in the Chair.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION REGARDING MOBILISING PUBLIC ENTHUSIASM AND SUPPORT FOR THE SECOND FIVE YEAR PLAN—*continued*

श्री देवकीनन्दन नारायण (मुम्बई) . आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव के

[श्री इबकीनन्दन नारायण]

उद्देश्य को देखते हुये मेरे खयाल से इसकी कोई मुखालफत नही कर सकता क्योकि इसका उद्देश्य साफ है कि प्लान को कामयाब करने के लिए जनता का अधिक से अधिक कोआपरेशन पैदा करना चाहिये और जिस जनता को सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से यानी सामूहिक विकास मे लाभ होगा, उस जनता को प्रथम जाग्रत करना चाहिये। तो इस उद्देश्य से कौन मुखालफत कर सकता है। परन्तु मेरे भाई अलगू राय शास्त्री जी ने सुबह किस बिना पर मुखालफत की, मै तो नही समझ सका। मैने समझने की कोशिश भी की, पर कुछ नही समझा। आखिर कोई यह तो नही कहता कि सरकार अपनी ओर से कोशिश नही कर रही है। काफ़ी कोशिश हो रही है, कामयाबी भी काफ़ी हुई है, परन्तु इसका मतलब यह नही है कि बहुत कुछ करना बाकी नही है। अभी बहुत कुछ करना बाकी है और जो कुछ बाकी है, यदि उसको कामयाब करना है तो जनता के कोआपरेशन की आवश्यकता है और इस प्रस्ताव मे यह बात साफ कही गई है कि जनता का मैक्सिमम कोआपरेशन पैदा करना चाहिये।

हमें यह देखना चाहिये कि आज प्लान की जिन चीजो का सम्बन्ध जनता से है, उन कामो मे जनता का कोआपरेशन प्राप्त हो रहा है या नही। बड़े बड़े कारखाने खुल रहे है, बड़े बड़े उद्योग चल रहे है, रेलें बन रही है, लोहे के कारखाने खुल रहे है, ये सब ठीक है। मै यह नही कहता कि यह नही हो रहा है, परन्तु जिन बातो से जनता का सम्बन्ध है, वहा पर हमे देखना चाहिये कि जनता का हमें पूरी तरह से कोआपरेशन मिल रहा है या नही। जहा तक मै देखता हूं, हमारे प्लान की आत्मा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स और नेशनल विकास प्रोग्राम्स है। यह जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, यह खासकर इस प्लान की आत्मा है। तो ये दो बातें ऐसी है जिनका सम्बन्ध पाच लाख गावो मे बसे हुये ८० फ़ी सदी हिन्दुस्तानियो से है। ठीक ही हमारे नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते है कि जब तक ग्रामों का सुधार नही होगा तब तक हिन्दुस्तान का विकास हो रहा है, यह कहना मुश्किल है। इस निगाह से आप देखेंगे तो कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का सबसे पहले गावो से सम्बन्ध आता है और इन कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में देखिये कि क्या हो रहा है। हर एक प्रान्त का तजुर्बा अलग अलग हो सकता है। मेरा भी कुछ तजुर्बा है। मै देखता हूं कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स का जो काम चल रहा है वह सरकारी अफसरों की मार्फत चल रहा है और जितना कोआपरेशन जनता का मिलना चाहिये या पैदा होना चाहिये वह न मिल रहा है और न पैदा हो रहा है। मेरी यह शिकायत है कि खास कर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में जो आफिसर है—खासकर मै अपने प्रान्त का तजुर्बा बयान करता हू—वे आम जनता और सरकार जो वालंटरी कार्यकर्त्ता है उनका कोआपरेशन लेने की कोई खास कोशिश करते है, ऐसा नही है। असल मे उनका कोआपरेशन नही चाहते और जो उनके हा नीचे नौकर लोग है उनसे वे काम करवाया करते है। हमे कम्युनिटी प्रोजेक्टस की ओर देखते वक्त यह देखना चाहिये कि जहा पर कम्युनिटी प्रोजेक्टस का काम हो रहा है वहा किस तरह की बेहतरी हो रही है। क्या वहां माली हालत सुधर रही है, क्या खेती की पैदावार वहां बढ़ रही है, क्या वहा ग्रामोद्योग बढ़ रहे है, क्या वहां घरो की कोई दुरुस्ती हो रही है, क्या वहा रूरल हाउसिंग में कोई सुधार हो रहा है, जब इस तरह की चीजे आप देखेगे तो आपको कहना होगा कि अभी दिल्ली बहुत दूर है।

प्लान का असली मकसद जो है वह यह है कि असम जनता को उससे लाभ पहुंचना चाहिये। मै तो यह नाप हाथ मे रखता हू कि जो आखिरी मनुष्य है, लास्टमैन आन दी लास्ट लैडर है, उसकी हालत किस तरह से दुरुस्त हो रही है, उसका कितना कोआप-

रेशन मिल रहा है और वह इसमे कितनी मदद देने के लिए तैयार है । मुझे आश्चर्य होता है जब कभी मै यह सुनता हू कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स से एक रेवोल्यूशन हिन्दुस्तान मे हो रहा है, एक काया कल्प हो रहा है । मुझे तो कही काया कल्प दिखाई नही देता और न कही रेवोल्युशन दिखाई देता है । माफ कीजियेगा, शायद मै ऐसे शब्द कहते वक्त कुछ बडे लोगो से अलग राय व्यक्त कर रहा हू, परन्तु यह बात बिल्कुल सत्य है । आप मेरे साथ चलिये, मै चलने के लिए तैयार हू और देखना चाहता हू कि कहा पर, किस प्रान्त मे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स की वजह से रेवोल्युशन या काया कल्प हो रहा है । काया कल्प हो यह हम भी चाहते है, परन्तु काया कल्प तो तब होगा जब आम जनता के विचारो मे, आम जनता के प्रयत्नो मे एक बनियादी तब्दीली हो जायगी और आम जनता इस कार्य को अपना समझ कर करने लगेगी । एवोल्युशन कमेटी जो बलवन्तराय मेहता जी की अध्यक्षता मे स्थापित हुई थी, उसकी रिपोर्ट आपने देखी होगी । उन्होने भी यह शिकायत की है कि इस काम मे राज्य सरकारो को जितना सहयोग देना चाहिये और जितनी उनको दिलचस्पी लेनी चाहिये, उतना न वे सहयोग दे रही है और न दिलचस्पी ले रही है । जब उनकी शिकायत यहा तक है कि राज्य सरकारे दिलचस्पी नही ले रही है, तो आम जनता के सम्बन्ध मे हम क्या खयाल कर सकते है ।

दूसरी बात यह है कि एक बजट पाच सात लाख का होता है जो ऊपर से बनाया जाता है और नीचे नाम के लिए पूछा जाता है । उसमें कहा तक सहयोग लोगों का रहता है यह आप सब लोग जानते है । इसी लिए उन्होने यह बात कही है कि यह सहयोग पैदा करने के लिये बहुत कुछ काम पचायतो के सुपुर्द करना चाहिये । यह बात जरूर है कि हमारे यहा प्रोजेक्ट एरियाज मे सडकें और रास्ते बन रहे है, स्कूल दुरुस्त हो रहे है, कुछ पंचायतो के मकान बन गये है, कुछ सामाजिक शिक्षा का भी प्रयोग हो रहा है, परन्तु गावो को आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह विकसित करने के लिये कोई टारगट्स बनाये गये हो और उन टार्गेटस तक पहुचने के लिए लोगो का प्रयत्न हो रहा हो, ऐसी बात कही दिखाई नही देती । यह तो तब दिखाई देगी जब लोगो का पूरा कोआपरेशन आप को मिल जायगा ।

जहा तक सोशल वैलफयर की बात है, सोशल वैलफेयर के बारे मे जितना थोडा कहा जाय, उतना ही अच्छा है । इसमे विशेष यह बात है कि सोशल वैलफेयर का सारा काम बहनो को सौपा गया है । यहा बहने दिखाई नही दे रही है, एक या दो बहने ही इस वक्त यहा पर है, परन्तु मै खास कर मिनिस्टर साहब के कानो तक यह बात पहुचाना चाहता हू कि यह सोशल वैलफेयर का काम जिन बहनो को सौपा गया है, वे अधिकतर क्लब लेडीज है, फैशनबिल लेडीज है, और यह काम उनके सुपुर्द होने के बाद शायद वे कभी देहात मे पहुची हो और खेत देखे हो, लेकिन इससे पहले उन्होने कभी खेत देखे हो, ऐसा मै नही समझता । (*Interruptions*) इस लिए जब आप देहातो का सुधार करना चाहते है, देहात की बहनो को ऊचा उठाना चाहते है तो आप ऐसी बहनो के जिम्मे यह काम करिये जिन को गावो की बहनो से आत्मीयता है । जिन बहनो मे आत्मीयता नही होगी, जिनमें एक तरह का ममत्व नही होगा, वे इस काम को ठीक नही कर पायेगी ।

श्री मैथिलीशरण गुप्त (नाम निर्देशित) : सावित्री जी से अपील कीजिये ।

श्री देवकीनन्दन नारायण जब गाव की बहने इन पडी लिखी और फैशनेबल बहनो को देखती है तो वे सकुचा जाती है और उनके पास जाना तक नही चाहती, यह मेरा तजुर्बा है और यह मैने देखा है । इस लिए मै खास कर यह कहना चाहता हू कि

[श्री देवकीनदन नारायण]

सोशल वैलफेयर काम को आप ऐसी बहनो के सुपुर्द कीजिये जिन्होने इस काम के लिए अपना समय और अपना जीवन कम या अधिक अर्पण किया हो सोशल वैलफेयर के बारे मे मुझे एक बात और कहनी है । आपने तमाम जीपें अधिकारियो को दे रखी है, आप ज़रा तलाश कीजिये कि इन जीपो का क्या होता है, इन जीपो मे कौन दौडते है, कौन प्रवास करता है और कितनी उनकी माइलेज होती है । ये तमाम बात आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सोशल वैलफेयर के नाम से बहुत कुछ जो काम हो रहा है, वह खास कर देहातो मे नाममात्र का ही हो रहा है ।

श्री शीलभद्र याजी अभी शुरूआत है ।

श्री देवकीनन्दन नारायण इसके बाद सोशल वैलफेयर .

(*Interruption*)

This is not unfair This is a statement of fact I told him just now मैने यह कहा कि हिन्दुस्तान मे ऐसी बहने मौजूद है जो इस काम को कर सकती है और वे योग्य है । मै यह नही कह रहा हू कि हिन्दुस्तान मे योग्य बहने नही है, परन्तु शहरो की बहनो, खास कर क्लब लेडीज़ को ऐसे काम सुपुर्द नही करने चाहिये, जिनका कि आज तक देहातियो के साथ कोई सम्बन्ध नही रहा और न उनके साथ आत्मीयता का भाव पैदा हुआ हो ।

इसके बाद खेती के बारे मे हमे कम्यनिटी प्रोजेक्ट्स एरिआज़ की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये जिससे उत्पादन बढे । परन्तु हिन्दुस्तान की खेती को देखते हुए, यह बात माननी पडती है कि सिर्फ खेती का उत्पादन बढाने से ही काम नही चलगा, उसकी भी मर्यादा है कि कहा तक बढ सकती है । हमारे गावो के किसानो को बडी मुश्किल स खेती में पाच छ महीने काम मिलता है और बाकी पाच, छ महिने बेकार रहते है इस लिये जब तक आप ग्रामोद्योगो का आश्रय नही लेगे तब तक आप पूरी तरह से खाली वक्त मे उनको उद्योग नही दे सकेंगे, न ग्रामो का भला ही कर सकेंगे । बहुत दिनो तक—मेरे ख्याल से पहले दो वर्षों तक—ग्रोमोद्योग का काम कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स के कामो में शामिल तक नही था । मेरे इस कथन में यदि गलती हो तो मिनिस्टर साहब दुरुस्त कर सकते है । शायद इस वर्ष से पहले वर्ष मसूरी मे या कही ओर काफरेस हुई थी, वहा प्रथम यह उपाय सोचा गया कि ग्रामोद्योग को भी खास स्थान दिया जाना चाहिये और कुछ ऐसे क्षेत्र—जिसे इटेसिव एरियाज़ के नाम से पुकारा जाता है—कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स में रखे जाने चाहिये कि जहा ग्रामोद्योग को प्रधानता दी जाय । मेरा कहना यह है कि जब आप गावो की, देहातो की, बात करते है तब आप को ग्रामोद्योगो का विकास करना चाहिये क्योकि उनको बढाने से और अधिक उत्पादन से ही हमारे किसानो की मदद हो सकती है ।

आपने देखा होगा, अभी अभी अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आई है, उस रिपोर्ट में हमारी अन्न की कमी की चर्चा करते हुये एक खास बात की ओर ध्यान दिलाया गया है । उसमे दो बातें कही गई है लेकिन मै एक बात की ओर आप का ध्यान खीचना चाहता हू और वह है फेमिली प्लानिग । इस रिपोर्ट मे हमे पता चलता है कि उत्पादन जितना बढता है उतना खर्च हो जाता है क्योकि उत्पादन जितना होता है उतने ही खाने वालो के मुह बढते जा रहे है । एक तरफ खाने वाले तो बढते जा रहे है परन्तु दूसरी तरफ उत्पादन कहा तक बढ सकता है इस लिये जब तक आप खाने वालो की पैदाइश को मर्यादा मे नही लायेगे तब तक अन्न की कमी जारी रहेगी । इसलिये प्लानिग कमीशन को इस चीज का खास कर देहातो मे प्रचार करना चाहिये क्योकि उन बेचारो में आज अज्ञान है .

(Time bell rings.)

I shall finish within five minutes.

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI M B. JOSHI): Not five minutes.

SHRI DEOKINANDAN NARAYAN: I did not know about it otherwise I would have been shorter.

तो ज्यादा से ज्यादा ज़ोर ग्रामों में देना चाहिये, शहरों में फ़ेमिली प्लानिंग पर आप ज्यादा ज़ोर क्यों देते हैं ? एक वक्त मैंने कहा था कि भागवानों को तो लड़के लड़कियां होने नहीं हैं, अधिकतर ग़रीबो के घर में दिखाई देती है । यदि फ़ेमिली प्लानिंग की ज़रूरत है तो गांवों में है ।

आप स्माल सेविंग्स की बात करते है । स्माल सेविंग्स आपको बहुत मिल सकती है, परन्तु उसको एकत्रित करने के लिये भी आपको कोआपरेशन की जरूरत है, देहातियों के कोआपरेशन की ज़रूरत है । अगर आप विद्यार्थियों में स्माल सेविंग्स का प्रचार करें, प्राथमिक स्कूल से ले कर कालेज के विद्यार्थियों तक में, तो मेरा विश्वास है कि कई करोड़ रुपया आप एकत्र कर सकते हैं । मेरे प्रान्त में एक जिले में एक आना, दो आना एकत्र करके यह प्रयोग किया जा रहा है । मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप ऐसा प्रोग्राम निश्चित करें कि प्राथमिक स्कूल से लेकर कालिज तक के विद्यार्थी साल में एक सप्ताह में एक बार ऐसा दिन मनायें जिसमें वे कुछ बचत करें, और उसे एकत्र करें, जैसे कि सिनेमा की बचत, होटल में न जाने से बचत, ऐसी बहुत सी बचतें है जो वे कर सकते हैं । इस तरह से आप विद्यार्थियों का कोआपरेशन लीजियेगा ।

इसके बाद, आपका जो प्रचार का कार्य है वह आप पार्लियामेंट के मेम्बरों से लीजिये, लोकल बाडीज, एसेम्बली के मेम्बरों से लीजिये उनके सुपुर्द यह काम आप करियेगा । आप यहां इश्तहार छपाते हैं, मासिक पत्रिकायें छपाते है जो कि ढेरों में राज्य सरकारों के दफ्तरों में पड़े रहते है और वे किसानों तक पहुंचते ही नहीं है । तो प्रचार का काम इन भाइयों को सौंपना चाहिये जो यहां बैठे हुये है । यदि आपको जनता का कोआपरेशन प्राप्त करना है तो वह काम आप जनता के नुमायंदों को सौंप दीजिये । अफ़सरों के ज़रिये आप बहुत कुछ कोआपरेशन प्राप्त कर सकते है, ऐसा मै नहीं मानता ।

अब आखिरी एक बात और मुझे कहनी है । हमारे साथी भाई पारिख साहब बोलने के लिये खड़े हुये तो उन्होंने पहले प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात शुरू की और आखिर में यहां तक उतर आये और कहने लगे, हमारे मिनिस्टर्स तो लेमैन है । तो क्या मेरे भाई चाहते है कि उद्योगपति बना दिये जायें मिनिस्टर्स । हां, हो सकता है पैसा कमाने का काम हो तो मैं भी कह देता कि उद्योगपतियों को मिनिस्टर बना दिया जाय । परन्तु पैसा कमाना कुछ और होता है और राज चलाना और बात हुआ करती है, यह मेरे भाई को जानना चाहिये, और इस तरह से यह कहना कि हमारे मिनिस्टर्स लेमैन है यह उनको शोभा नहीं देता । *(Time bell rings).* पैसे की बदौलत सब काम नहीं हुआ करते हैं ।

आखिर में मेरी यही प्रार्थना है कि अगर जनता मे कोआपरेशन का भाव पैदा करना है तो जनता के ही नेताओं को, जनता के ही नुमाइन्दों को जनता के पास जाना होगा और जनता से सहकार मांगना होगा । तब ही उसका सहकार मिल सकता है । इसमें जितनी मदद सरकार कर सके, करे । सिर्फ सरकार के ओहदेदार कोआपरेशन प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा मेरा तजुर्बा है ।

श्री पां० ना० राजभोज (मुम्बई) : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव हाउस

[श्री पां० ना० राजभोज]

के सामने प्रस्तुत किया गया है, मेरे खयाल मे उसकी कोई ज्यादा आवश्यकता नही थी। लेकिन शासन द्वारा इस सम्बन्ध मे किये जाने वाले कार्य के विरुद्ध जो आवाज विरोधी दल लगा रहा है वह सर्वथा वृथा है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना तीन भागों में विभाजित होती है। । एक तो मेरे खयाल से मेजर प्रोजेक्ट्स अर्थात् बडी योजनाये है। दूसरे हैवी इंडस्ट्रीज अर्थात् भारी उद्योग और तीसरे कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स अर्थात् समाज विकास। मेरे खयाल से जो पहली दो बातें मैंने बताई यानी मेजर प्रोजेक्ट्स और हैवी प्रोजेक्ट्स, उसके लिये विशेष रूप से शिक्षा पाये हुये यंत्र और तंत्र विशारदो की आवश्यकता होती है। जो तीसरा भाग है समाज विकास का, इसके बारे मे हम लोगो को पबलिक का ज्यादा से ज्यादा सहकार मिलने की बहुत आवश्यकता है और इसके लिये प्रचार होना चाहिये। गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको भी मालूम होना चाहिये कि यह जो पंचवर्षीय योजना है वह किस तरह से अमल मे आनी चाहिये। योजना का काम चलाने के लिये इस समय हमे विदेशो से अनुभवी, प्रशिक्षित विशारदो की सहायता लेनी पड़ती है। जहा तक समाज विकास का सम्बन्ध है उसमे हमे केवल जनता का सहयोग, जनता की सहायता, जनता का श्रम चाहिये और उसके लिये हमे उनमे काम करने की लगन और उत्साह जाग्रत करने की आवश्यक्ता है। देश के ३८ करोड लोगों के ७६ करोड हाथो की श्रम शक्ति पर हमारी योजना की सफलता निर्भर है और सरकार इस ओर जितना ध्यान अब तक दे रही थी मैं समझता हू कि उससे और अधिक ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जिस दृष्टि से हम लोग चाहते है उस दृष्टि से सरकारी अधिकारी और जो जनता है, वह हमारी योजना के महत्व को देखते नही है। हम यहां कइ बड़ी बड़ी बात करते है लेकिन हमारे ५, ७ लाख देहातों की ग्रामीण जनता के उद्धार के लिये उनसे जितना श्रम लेना चाहिये उतना श्रम सरकार उनसे लेती नही है। हमारे मंत्री महोदय पबलिक वर्कर है और वे समझते है कि उनका ज्यादा से ज्यादा विश्वास हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह काम केवल निःस्वार्थी समाज सेवकों द्वारा ही ठीक से हो सकता है जिनकी हमारे देश में कमी नही, परन्तु 'राइस सोलजर्स' पेट पालतू लोगों की फौज जमा करके यह काम नहीं हो सकता लेकिन उनमें से आदर्श सेवक और सेविका निर्माण करना चाहिये। तो यदि सरकार समाज सेवी संस्थाओं के जरिये से ज्यादा से ज्यादा सहकार लेना चाहे तो हम उनको देन के लिये तैयार है।

तीसरी बात जो मुझे कहनी है वह हरिजनोद्धार, शराबबन्दी, गदी बस्तियां, समाज-कल्याण, आदिवासियों के कल्याण और ग्रामोद्धार आदि जो अनेक महत्वपूर्ण बातें है, उसके बारे में है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस कार्य को करने वाला जो अधिकारीवर्ग है वह इतना काम नहीं कर रहा है जितना कि उसे करना चाहिये। उसे अधिक ध्यान दे कर इस कार्य को करना चाहिये। अधिकारीवर्ग में से ऐसे अनेक लोग पाये जाते है जो केवल हरिजनों के हितों की उपेक्षा करते है और समय समय पर अपने कामों के द्वारा वे किसी हद तक अस्पृश्यता का पालन करते है, इसका परिचय देते है। श्री देवकीनन्दन नारायण जी ने समाज कल्याण बोर्ड के बारे में जो बाते कही उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि इस बोर्ड में इस समय ज्यादा बहने ही काम कर रही है। इसमे फैशनेबुल औरते ही ज्यादा है। मेरा तो यह खयाल है कि हरिजनोद्धार और समाज कल्याण बोर्ड मे देहात के रहने वालों को काम करना चाहिये क्योंकि वे ही उनके बारे मे ज्यादा जानते है। इस समय इन संस्थाओं में बहुत अच्छे कार्यकर्त्ता है, लेकिन मैं बम्बई के बारे मे बतलाना चाहता हू कि बम्बई

के पूंजीवादी और बड़े अफ़सरों की औरतें, जिन्होंने कभी देहाती इलाका नहीं देखा है, समाजकल्याण बोर्ड में है । मुझे मालूम नहीं कि यह महिला जो कि मोटर में हर समय घूमती है देहात में क्या काम कर सकेगी । इस महिला को देहात के कष्टों के बारे मे क्या मालूम होगा ? इसलिये मेरा कहना है कि जो लोग समाज की उन्नति चाहते है, वे उनकी कठिनाइयों को भली भांति समझते है उन्हे यह काम करने को देना चाहिये । हमारे हरिजन और आदिवासियो में बहुत सी बहने है जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती है और अच्छा काम कर सकती है । इसके विपरीत होता यह है कि महाराष्ट्र में समाज कल्याण बोर्ड मे गुजरात का आदमी आना चाहता है । इस बेचारे को यह भी मालूम नही है कि कौन हरिजन है, कौन आदिवासी है । इस तरह का काम कुछ लोगों ने कभी भी नही किया है, फिर भी उन्हें यह काम सौपा जा रहा है । मेरी प्रार्थना यह है कि इस कार्य मे उन ही लोगो को लगाया जाना चाहिये जो कि इस काम मे सम्बन्ध रखते हों । इसके साथ ही साथ मै यह भी प्रार्थना करूंगा कि सरकार इन कार्यो के लिये ज्यादा धनराशि दे ताकि यह काम अच्छी तरह से किया जा सके ।

चौथी बात जो मुझे कहनी है वह ग्रामोद्योग के सम्बध मे है । इस योजना काल मे यह कार्य किया जा रहा है जो योग्य है । मेरी प्रार्थना यह है कि जिनको सचमुच विकास और उन्नति की आवश्यकता है उनको इसमे स्थान नही दिया जाता है । इसके विपरीत यह हो रहा है कि ऐसे तत्वों को स्थान मिलता है जिन्हे उसकी जरूरत नही है । मेरा ख्याल यह है कि ग्रामोद्योग का जो कार्य हो रहा है उसमें चर्म उद्योग को उचित स्थान नही मिल रहा है । आज करोडो रुपया सरकार चर्म उद्योग के बारे मे खर्च कर रही है मगर देहातो में इस काम मे लगे हुये लोगों को कोई उत्तेजना नहीं मिलती है । हमारे मंत्री महोदय इस काम में बहुत दिलचस्पी लेते है, मुझे आशा है कि वे उद्योग की कठिनाइयो को दूर करने की कोशिश करेंगे ।

बहस के दौरान साधु समाज के बारे में बात कही गई । मेरा अपना ख्याल यह है कि पुराने ख्याल के जो लोग है अगर वे किसी अच्छे काम में अपना सहयोग देना चाहते है तो अच्छी बात है । इसी तरह से अगर साधु समाज भी सहयोग देना चाहता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है । लेकिन आप जानते है कि आज देश मे जलसा करने वाले बहुत लोग है जो कि कोआपरेशन करने को तैयार है । आज हमारे देश में कई प्रकार की शक्तिया है जो कि राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के लिये काम करने को तैयार है । इन सब को बढ़ावा मिलना चाहिये और हर तरह का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये । मगर जिन संस्थाओं में जाति भेद की भावनाये अभी तक मौजूद है उन्हे इस तरह का प्रोत्साहन नही दिया जाना चाहिये । अभी हाल मे अहमदाबाद में जो साधू समाज का सम्मेलन हुआ था उसमें साधु लोग हरिजनो के साथ बैठने को तैयार नही हुये । जब इन लोगों में इस तरह की मनोवृति है तो यह किस तरह से देश का सुधार कर सकेंगे ? जिन संस्थाओं मे इस तरह की भावनाये अभी तक मौजूद है वे किसी तरह से भी जनता की भलाई नही कर सकते है और सरकार को भी उन्हें प्रोत्साहन नही देना चाहिये ।

अब मै गंदी बस्तियो के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । आज हमारे देश में कई प्रकार की गंदी बस्तिया है और उनका सुधार करने के लिये कई प्रकार की शक्तिया कार्य कर रही है । लेकिन फिर भी देश मे काफी गंदी बस्तिया पड़ी है जिन पर कई प्रकार से खर्च करने की आवश्यकता है । पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे नेता, हर वक्त, बार बार कहते हैं

[श्री पां० ना० राजभोज]

कि ये गंदी बस्तियां हमारे देश के लिये एक कलंक हैं। जिस प्रकार हरिजनों के लिये अस्पृश्यता कलंक है उसी प्रकार देश के सामाजिक जीवन के लिये गंदी बस्तियों का नष्ट किया जाना आवश्यक है। मेरी इस सम्बन्ध में यह प्रार्थना है कि बम्बई पूना और दिल्ली तथा अन्य प्रांतों में जितनी भी गंदी बस्तियां हैं उन्हें हमें जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिये। हरिजनों और आदिवासियों की जितनी भी गंदी बस्तियां इस समय देश में हैं वे जल्द से जल्द खत्म होनी चाहियें। मेरे पास इस समय इस सम्बन्ध में कहने के लिये ज्यादा समय नहीं है लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि देश के कार्यकर्ताओं और समाज सेवकों को अपने विश्वास में लेकर, देश में इस कार्य को करने के लिये जितने भी योग्य आदमी मिलते हैं, उनको साथ लेकर इस कार्य को कार्यान्वित करना चाहिये अंत में मैं फिर यह कहूंगा कि ग्रामोद्योग गंदी बस्तियों, समाज सुधार और नशाबंदी के सम्बन्ध में जो कुछ सुझाव दिये हैं उन्हें मंत्री महोदय अमल में लाने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती सावित्री निगम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ा और पढ़ने के पश्चात् मुझे प्रतीत हुआ कि यदि इस प्रस्ताव को मूव करने वाले महोदय ने गवर्नमेंट स्पोक्समैन और देश के मौजूदा नेताओं के वक्ताओं को ध्यान से पढ़ा होता तो शायद वे कभी भी इस प्रस्ताव को मूव करने की आवश्यकता महसूस न करते।

श्रीमन्, पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में ही हमारे देश के कर्णधारों ने इस आवश्यकता को भलीभांति समझ लिया था और इसलिये उन्होंने भारत सेवक समाज जैसी एक विशाल संस्था का निर्माण किया, जिस का चर्म उद्देश्य लोगों से वालंटरी कोआपरेशन लेना था। जन जन से सहकार लेना था और इस दृष्टि से जितनी भी योजनायें उसके क्षेत्र में संभव हो सकती थीं, बनाई गई थीं। इस प्रकार के देश के छोटे बड़े सभी शहरों में, गांवों में, जिलों में, भारत सेवक समाज की शाखायें खुल गई। जिनके हृदय में देश प्रेम की आग थी, जिनके मन में देश सेवा के लिये विकलता थी, वे सभी लोग शामिल हो कर इसमें सहयोग दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि जितना वालंटरी कोआपरेशन हमें उन योजनाओं के लिये मिलना चाहिये था, वह सब हमें मिल चुका है और अब हम आगे प्रयत्नशील नहीं हैं। लेकिन जिस बात को आज हमारे चोटी के नेता बार बार खुले तौर पर दोहराते रहते हों उसको प्रस्ताव के रूप में लाकर रखने में सदन का समय नष्ट करने के सिवाय कोई बात दिखाई नहीं देती है।

श्रीमन्, सोशल वेलफ़ेयर बोर्ड के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह भी कहा गया है, कि सोशल वेलफ़ेयर बोर्ड में फैशनेबल स्त्रियां काम करती हैं। मैं माननीय मेम्बर से पूछना चाहती हूं—स्त्रियों की बात तो जाने दीजिये कौन सा ऐसा आदमी है जो फैशन नहीं करता, तेल नहीं लगाता, मुंह में सफेदी नहीं लगाता और चमरौध जूता नहीं पहिनता। मुझे ऐसा व्यक्ति बता दीजिये जो आजकल फैशन नहीं करता है? ऐसी स्त्रियों को जो कि कायदे में रहती हैं क्या उन्हें भगवान ने ऐसा बना कर आउट राइट कंडेम कर दिया है।

(Interruptions.)

3 P.M.

मैं यह विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हूं कि फ़ैशनेबल स्त्रियों को बहुत बड़ा अवसर मिला है कि वे गांवों में जा कर लोगों की सेवा कर सकें और फिर जहां तक फैशनेबल स्त्रियों का सम्बन्ध है वे भी हमारे देश की बहनें हैं। कुछ माननीय सदस्यों

ने यह कहा कि वे काम नही करती है, मोटरो मे चढती है, परन्तु यदि वे पर्दा नही करती है और गावो मे लोगो की सेवा करने के लिये जाती है तो यह देश के लिये बडा शुभलक्षण है ।

(*Interruptions.*)

मै इस तरह के डिस्टरबेंस की बिलकुल परवाह करना नही चाहती । मै बराबर अपनी बात कहती जाऊगी ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. B JOSHI): No interruptions.

श्रीमती सावित्री निगम : श्रीमन्, यह हम सभी चाहते हैं कि हमे गाव की बहनो और ग्रामीणो की मदद करनी चाहिये, लेकिन इस सम्बन्ध मे मै आपके सामने एक उदाहरण देना चाहती हू । यहा दिल्ली मे एक सोशल वेलफेयर बोर्ड है और उसकी हालत पर जरा विचार कीजिये । भारत सेवक समाज ने यहा एक प्रोजेक्ट ले रखा है । हम लोगो ने पूरा प्रयत्न किया कि अगर हमे ग्रामीण बहने मिल सके, तो चाहे उनकी क्वालिफिकेशन कम हो क्यो न हो, फिर भी हम उनको रख ले, और शहर की एक बहन को भी हम वहा गावो मे न ले जाय, लेकिन आप विश्वास कीजिये कि तमाम प्रयत्न करने पर भी मुश्किल से १० प्रतिशत ऐसी बहने मिल पायी जो कि गावो मे काम कर सकती हो । हम ऐसी ग्रामीण स्त्रियो का भी स्वागत करने के लिये तैयार थे जिन की क्वालिफिकेशन भले ही कम हो, लेकिन फिर भी वे नही मिल सकी । ऐसी दशा मे कम से कम जिन स्त्रियो को क्लब लेडीज़ कहा गया, उनके हृदय मे तो देश प्रेम जाग्रत हुआ और वे गावो मे जा कर सेवा करने के लिये प्रस्तुत हुई । एक भाई ने मुझ से पहले कहा कि ये बटरफ्लाइज़ क्या काम करेगी । इसी लिये मैने उनसे कहा कि आप बटरफ्लाइज नही पसन्द करते है तो क्या कैटरपिलर्स पसन्द करते है । तो बजाय इसके कि आप बटरफ्लाइज़ और कैटरपिलर्स की बात पर जाये, आपको उनके सेवा के काम को देखना चाहिये । मै विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहती हू कि वे चाहे जिस ढग का कपड़ा पहनती हो, लेकिन उनकी सेवा भाव मे कोई त्रुटि नही है और वे बहुत अच्छी तरह से सेवा का कार्य कर रही है । जहा तक यह प्रश्न है कि गाव की बहनो की उपेक्षा होती है, मै चाहती हू कि जो भी ऐसी गाव की बहने है जो सेवा कर सकती है, उनका नाम और उनकी सूची सदस्य महोदय, दे । मै उनकी सूची मिसेज़ देशमुख के पास भेज दूगी और मुझे आशा है कि वे उनकी पूरी मदद करेगी, क्योकि सोशल वेलफेयरबोर्ड का परम उद्देश्य ही यह है कि गाव गाव मे एक नयी क्रान्ति का सृजन किया जाय जिसमे एक एक झोपडी के द्वार पर एक नयी क्राति का आवाहन हो और एक एक झोपडी मे सेवक पहुचे । भारतमाता ग्रामवासिनी है और जब तक यह नही होगा तब तक इस सोशल वेलफेयर बोर्ड का एक भी उद्देश्य पूरा नही होगा ।

जहा तक सोशल वैलफेयर बोर्ड मे परिवर्तन लाने का प्रश्न है कि गाव के लोगो को भी अवसर देना चाहिये, मै समद् सदस्यों से सर्वथा सहमत हू कि वैसा ही होना चाहिये । यह नही होना चाहिये कि एक रिजिड सा नियम बन जाय कि एक बार जो व्यक्ति सोशल वैलफेयर बोर्ड मे आ गया वह सदा बना रहे । समाज मे जो पढी लिखी और योग्य बहने है उनको भी काम करने का अवसर मिलना चाहिये ।

इस सम्बन्ध मे मै एक बात कहे बिना नही रह सकती कि जहा भी पब्लिक कोआपरेशन की बात चलती है वहा एक सब से बडा प्रश्न जो पब्लिक कोआपरेशन का है वह इगनोर कर दिया जाता है । आप एक छोटी

[श्रीमती सावित्री निगम]

सी चीज़ देख लीजिए । यहा दिल्ली मे एक प्रोहिबिशन बोर्ड था और उसके मातहत एक इम्प्लीमैंटिग कमेटी बनी हुई थी । उसका काम मोहल्ले मोहल्ले मे बोर्ड की शाखाये खोलना था और हर मोहल्ले मे चार पाच आदमियों की कमेटी बना कर जो लोगो मे सोशल सर्विल्स होती थी या जो लोगो मे शराब गाजा, चर्स आदि नशे पीने की आदते होती थीं उन आदतो को समझा बझा कर छुडाना और हर तरह की सोशल और इकोनामिक मदद करना था । लेकिन जब दिल्ली स्टेट अमलगमेट हुई और यूनियन टेरीटरी बनी तो ऐसा अच्छा काम करने वाला बोर्ड भी खत्म हो गया और फिर वह पुनर्जीवित नही किया गया । मैने इसी सदन मे जब प्रश्न किया कि वह बोर्ड क्यो नही पुनर्जीवित किया गया, तो यह उत्तर दिया गया कि सरकार उसकी आवश्यकता नही समझती । यह बडी खेदजनक बात है कि यह मानते हुये कि उस बोर्ड ने एक साल मे इतना महत्वपूर्ण कार्य किया कि उसने मोहल्ले मोहल्ले मे और गली गली मे अपना प्रभाव फैला दिया और हजारो बिगडे हुये घरो को सुधार दिया, फिर भी जनता का कोआपरेशन नही लिया जा सका । इस तरह सैकडो आदमियो का वालटरी को-आपरेशन मिल रहा था, सैकडो कार्यकर्ता नशेबन्दी का काम नि शुल्क और बिना वेतन लिये करने के लिय तैयार हो गये थे, लेकिन उस बोर्ड को खत्म करके जो लोगो का वालटरी कोआपरेशन मिल रहा था उसको सरकार ने बन्द कर दिया ।

श्रीमन्, मै एक बात और कहना चाहती हू और वह यह है कि अगर हम सचमुच चाहते है कि हमे जन-जन का वालटरी कोआपरेशन मिले तो जो मैने एक योजना प्लानिग कमीशन को भेजी थी, उसे सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिये । उस योजना मे मैने इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था कि सरकार को परिश्रमालय खोलना चाहिये और हर व्यक्ति को, चाहे वह एजुकेटेड अनएम्प्लायड हो या अन-एजुकेटेड अनएम्प्लायड हो जब तक उसको नौकरी न मिले, उस परिश्रमालय मे छ· या आठ घटे सूत कातने या दूसरा किसी किस्म का काम देना चाहिये और उसके बदले मे उसको कम से कम भोजन दे देना चाहिये । उसमे उसको समाज सेवा की भी ट्रेनिग दी जा सकती है । इस तरह का एक कैम्प यहा पर जरूर शुरू हुआ है लेकिन मुझे पता नही है कि वह किसी योजना के मातहत शुरू किया गया है या मेरी योजना से ही प्रेरणा लेकर वह "वर्क रिओरियटेशन कैम्प अडर दी लेबर मिनिस्ट्री " शुरू किया गया है । चार पाच सौ नवयुवको को उसमे ट्रेनिग दी जाती है । लेकिन मै यह चाहती हू कि ऐसे कैम्प हर शहर मे खोले जाये ताकि जो नवयुवक नौकरी की तलाश में इधर उधर दफ्तरो मे दौडते दौडते परेशान हो जाते है उनको एक नई रोशनी मिल सके । तो आवश्यकता यह है कि ऐसे परिश्रमालय हर शहर और हर गाव मे खोले जाय ताकि हर नवयुवक को पता चल जाय कि उसका भविष्य आशामय है । वह यह समझे कि यद्यपि उसे आज काम के बदले पैसा नही मिल रहा है, लेकिन उसको जो ट्रेनिग मिल रही है, उसके कारण उसका सुन्दर भविष्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा है । मै चाहती हू कि आनरेबिल प्लानिग मिनिस्टर साहब मेरी इस दरख्वास्त पर जरूर ध्यान दे । जो योजना मैने भेजी थी वह फाइलो मे किसी बडल के नीचे दबी पडी होगी, लेकिन मुझे आशा है कि वे उसे निकलवा कर जरूर उस पर गौर करेगे । आज हमारे नवयुवक अनएम्प्लायड होकर रिऐक्शनरी फोर्सेज के हाथ मे पड जाते है, हुडदगा मचाने वाले लोगो के हाथ मे पड जाते हैं, ऐसी पार्टियो के हाथ मे पड जा। है जो कि उन्हे बरगला कर यूसलेस सिटिज़न बना देती हैं, उनके जीवन को बिलकुल निष्क्रिय बना

देती है । इससे अच्छा यह होगा कि ये हमारे देश के भावी नेता अच्छी तरह की ट्रेनिंग लें, अच्छे सम्पर्क में रहें जिससे उनको अच्छे विचार मिलें और साथ ही साथ एक नयी आशा की रोशनी का उनके जीवन में उदय हो । धन्यवाद ।

श्री ए० बी० कुन्हम्बु (केरल) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं लेकिन वालटरी, एफर्ट केवल कहने से कोई फायदा नही मिलेगा । जिन लोगों को वालंटरी एफर्ट करना हो, उनको कुछ मिलना भी चाहिये । हम इस मुल्क में कई तरह की कमेटियां आर्गेनाइज करते रहते है, लेकिन उनका काम आफिशल ही करते रहते है । मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट आफिशल्स का कंसेप्शन पूरी तरह बदलना चाहिये ।

जब तक हम ऐसा नही करेंगे तब तक कभी वालंटरी एफर्ट नही होगा । मै सिचाई के बारे मे ही एक एग्जाम्पल देता हूं । हमारे यहा हर एक गाव में कई तालाब है, कुये है और उनमे से कीचड़ और मिट्टी निकाल देने से अच्छी तरह से पानी मिल सकता है और इस पानी से सिंचाई हो सकती है । लेकिन हमारे इंजीनियरों मे पूछो तो वे कहेंगे कि इंजीनियरिंग के काम मे इसको सिंचाई नहीं कहते है । सिचाई को संस्कृत मे कहते है "जलसेचन" । जल से पानी सीचन की क्रिया को जलसेचन कहते हैं । यह काम तालाब से भी लिया जा सकता है, कुये से भी लिया जा सकता है । फिर भी हमारे इंजीनियर लोग इस तरह की सिचाई को सिचाई नही मानते ।

केरल मे हमने हर एक ज़िले मे कमेटी आर्गनाइज की हुई है । हर-एक महीने में उसका सम्मेलन होता है और तरह तरह के काम वह करती है । ये कमेटिया सोशल प्रोग्राम बनाती रहती है और अस्पताल भी कायम करती है । मै अपने यहां के एक एक गाव का उदाहरण द कि वहां केवल ६०० आदमी रहते है । लेकिन उन्होने २५ हजार रुपया कमा कर उसको एक बडी इमारत बनाने मे खर्च कर दिया । उसके बाद यह इमारत अभी हाल ही मे केरल गवर्नमेन्ट को सोंप दी है । इसी तरह से १०००० रु० खर्च करके एक इमारत बनाई---उसका नाम गांधी मंडप है---वह भी अभी केरल गवर्नमेंट को सोंप दी गई । इसी तरह और गांवों में कोआपरेशन और मिहनत से काम होता है । तो भी गवर्नमेन्ट आफिशियल्स के बर्ताव और उनके कंसेप्शन के कारण इन मेहनत करने वाले लोगो को आगे बढ़ने की आशा नही होती । मै कहता हूं कि द्वितीय पचवर्षीय योजना चलाने के कार्य में विजय पाने के लिये पबलिक कोआपरेशन और वालंटरी एफर्ट की बहुत जरूरत है । यह भी सोचने की बात है कि जनता किस तरह से कोआपरेट करे ? इस मुल्क में ७५ परसेंट तो हमारे किसान लोग है । यहा करीब १३ करोड एकड़ जमींन ऐसी है जो निकम्मी पडी रहती है और इसको किसानों को देने के लिये कोई कोशिश नही करता, कोई हिम्मत नही करता । अगर यह १३ करोड़ एकड़ ज़मींन किसानों को खेती के लिये मिल जाती तो वे कुछ करते भी, हमसे भी सहयोग करते और खेती की उपज भी बढ़ाते । हमारी खाद्य स्थिति बहुत मुसीबत मे है और इसलिये भी हमें ऐसा करने की जरूरत है । मै कहता हूं कि वालंटरी एफर्ट सिर्फ कहने से ही कोई फायदा नही, इसको अमल मे लाना चाहिये । लेकिन ऐसा नहीं होता । अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विजय न पा सके तो हमारे मुल्क को बहुत तक्लीफों का सामना करना पडेगा और यह बहुत ही रंज की बात होगी । तो विजय पाने के लिये हमे काम भी चलाने चाहियें, लेकिन वह तो कभी होगा नही । म कहता हूं हमारे देश के लोगों के लिये ोजना की जानका ी कराने के लिये एजुकेशन जरूर होनी चाहिये । हमारे मुल्क मे चारों

[श्री ए० बी० कुन्हम्बु]

और सेमीनार हो रहे हैं जिनमें दूसरी पंचवर्षीय योजना की सभी बातों के बारे में पढ़ना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं और उम्मीद है कि उसमें सभी लोग शामिल होंगे ।

केरल के बारे में कहते वक्त मुझे एक बात और कहनी चाहिये । हमारे माननीय सदस्य पारिख जी ने कहा वहां कम्यूनिस्ट गवर्नमेंट अभी हकूमत कर रही है और वह इंडिविजुअल लिबर्टी सप्रेस करेगी । मैं कहता हूं कि खुले दिल से वे केरल में जाकर सभी कामों को देखें कि वहां क्या हो रहा है और कम्यूनिस्ट हकूमत को अंधी आंखों से न देखें । मै कहता हूं कि यदि वे खुले दिल से देखेंगे तो उनको अपना खयाल बदलना पड़ेगा । वहां की कम्यूनिस्ट सरकार इंडिविजुअल लिबर्टी को सप्रेस नहीं करती । और दूसरे देशों के बारे में मै नहीं सोचता, मैं अपने देश में बैठता हूं । मै अपने देश के बारे में बातचीत करता हूं और फिर केरल में जो कम्यूनिस्ट सरकार कायम हुई है वह तो हमारे कांस्टिट्यूशन के मुताबिक़, उसके अनसार ही क़ायम हुई है । वहां कैसे कोई इंडिविजुअल लिबर्टी को सप्रेस करेगा ?

श्री जसौद सिंह बिष्ट : वह तो कांस्टीट्यशन का फंडामेंटल राइट है ।

श्री ए० बी० कुन्हम्बु : ठीक है । तो भी केरल के बारे में और कम्यूनिज्म के बारे में इस तरह से कहने से कोई फायदा नहीं होगा । लेकिन ये लोग पिछले ज़माने की बातों को ज़रूर कहेंगे और आजकल की स्थिति इंटरनेशनल स्थिति को नहीं देखेंगे । वे अंधी आंखों से कम्यूनिस्ट सरकार को देखते हैं । मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता । तो इस प्रस्ताव में हमारे सदस्य महोदय ने जो कुछ मेंशन किया है वह बहुत ठीक है । मैं चाहता था कि गवर्नमेंट आफिसर को सब तरह से अपना आउटलुक चेंज करने का भी इसमें जिक्र होता । हम अपनी पबलिक को साथ ले कर उसकी सहायता से आगे बढ़ सकते हैं ।

हमने अपने यहां हर एक ब्लाक में ब्लाक एड्वाइज़री कमेटी आर्गनाइज़ की है । मेरा सजेशन यह है कि पंचायत बोर्डों को अपने इलाके के अन्दर जो जो भी इरीगेशन या और तरह के प्रोजेक्ट करने हों उनको पूरा करने का अधिकार सौंप देना चाहिये । हमें पंचायत बोर्डों को अपने विश्वास में लेना है और उनके ज़रिये ही अपने सारे प्लान तैयार करने और उन्हें पूरा कराने का काम कराना चाहिये । उन कामों को करने के लिये उन्हें मिहनताना के तौर पर कुछ पैसा देना होगा ताकि वे ज्यादा ईमानदारी से अपना काम कर सकें ।

(Time bell rings.)

श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिंह (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आज सदन के सामने है, उसका उद्देश्य, उसकी शब्दावली ऐसी है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि शुबहा और संदेह की गुंजायश नहीं है । मैं यह मानता हूं कि यह प्रस्ताव अधिकारपूर्ण नहीं है और न कोई पेनेशिया है जिससे हमारे सभी दुख दर्द दूर किये जा सकें । योजना के इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमारे माननीय प्रधान मंत्री और उनके दूसरे साथी मंत्री बार बार लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि यह सारी योजना तब ही सफल होगी जब देश का जन-सहयोग प्राप्त होगा । इस प्रस्ताव के ज़रिये जन सहयोग की ही याचना की गई है । इस प्रस्ताव को पास कर देने से यह याचना पूरी हो जायेगी और गिरा देने से जो दूसरे विचार के लोग है, उनकी आशा पूरी हो जायेगी । मैं दोनों बातों में से किसी को नहीं मानता हूं । पर मैं एसा समझता हूं कि समय समय पर ऐसे प्रस्ताव के ज़रिये इस महत्वपूर्ण सदन में जहां देश के चने हुये लोगों के ज़रिये चुने हुये सदस्य भेजे गये हैं,

उनके भीतर विचार विमर्श हो, तबादला-ए-ख्यालात हो, तो इससे लाभ होने के बदले किसी तरह की हानि हो, ऐसा मुझको नही दीखता है । मै समझता हू कि हम सबो को माननीय सक्सेना साहब के इस प्रस्ताव के लिये जिसे माननीय मल्कानी साहब ने हमारे सामने रखा हे, आभारी होना चाहिये और इसकी निन्दा नही करनी चाहिये । इतनी देर से हमने एक दूसरे के विचारो को सुनन का अवसर प्राप्त किया और उससे मुझ लगता है कि कुछ लाभ अवश्य होना चाहिये । इस अवसर पर मै भी उचित समझता हू कि मुझको सामुदायिक विकास योजनाओ तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खडो के क्षेत्रो मे जो कुछ काम करने तथा देखने का अवसर मिला है, उसका कुछ अपना तजुर्बा मै सदन के अपने माननीय सदस्यो के समक्ष और आपके सामने रख दू ।

मैंने विकास खडो मे और सामुदायिक विकास क्षेत्रो मे अच्छे से अच्छा काम होते देखा है और मुझे यह भी देखने का अवसर मिला है कि कही कही केवल कागजो के ऊपर ही टार्गेट पर पहुचने की चर्चा होती है । मै इस निष्कर्ष पर पहुचा हू कि काम वहा अच्छा हो सका है जहा के विकास अफसर और कार्यकर्ता विकास माइनडेड है । साथ ही साथ जहा सरकारी कर्मचारी ऐसे रहते हो जो अपने को देहात वालो से घुला-मिला लेते है, सम्पर्क और अपनापन स्थापित कर लेते है, वहा काम अधिक अच्छा हो सका है । साथ ही साथ मेरा तजुर्बा यह है कि जिन क्षेत्रो मे बहुत सीधे-साधे लाग रहते है—बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र मे मुझे दौरा करने का अवसर मिला उडीसा मे चार दिन तक सेमिनार भी मैंने देखा—जहा हमारे अपढ आदिवासी बन्धु रहते है, *वहा काम करने मे लोगो को अधिक सफलता* मिल सकी है । अगर कार्यकर्ता उत्साही मिल जाते है तो उनके दिल मे उत्साह और लगन पैदा कर देते हैं । ऐसे कार्यकर्ता उनकी तहजीब का ख्याल रखते है, उनके कल्चर को अपने मस्तिष्क मे रखते है । उनके गाने, बजाने, नाच आदि सब को प्रोत्साहन देते है । उनके हृदय को वे छूने की चेष्टा करते है जिसमे उन्हे खूब अच्छी सफलता मिलती है । किसी किसी स्थान मे मैंने देखा कि लोग वहा के विकास कार्यकर्ताओ की भूरि-भूरि प्रशसा करते पाये गये है । हा, ऐसा मै देखता हू कि जो तथाकथित एडवान्स लोग कहे जाते है, ज़ो अच्छे पढे-लिखे लोग है, जिनमें तमाम कामो मे टीका टिप्पणी करने की आदत होती है, उनके कारण काम कम *हो पाता है । ज़रूरत इस बात की अवश्य* है कि हम इस बात के कायल हो कि काम करने वाला जो परसोनल चुना जाय, वह सिर्फ इस मतलब मे न चुना जाय कि बेकारी की समस्या हल हो रही है, एक ग्रेजुएट को इम्पलायमेट मिल रहा है । लोग इस मतलब से चुने जाय, उसकी परख इस कसौटी पर हो कि वे देहात के लोगो के साथ घुल-मिल कर काम कर सकेगे यानी उनके भावो का स्पष्ट अध्ययन कर सकेंगे, उनके दिलो को छू सकेगे । साथ ही साथ जो अफसर विकास क्षेत्रो मे काम करते हैं, व सचमुच लगनशील व्यक्ति होने चाहिये । ऐसे व्यक्तियो को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । उनकी पदोन्नति होनी चाहिये । ऐसा न हो कि एक आदमी मेहनत से काम कर रहा है और जब पदोन्नति का वक्त आये तो सिविल लिस्ट उठा कर यह देखा जाय कि उसका स्थान कितनी दूरी पर है । मैंने अपनी आखो से इस तरह के केसेज़ देखे है । मै यहा पर उस अफसर के बारे में कुछ अधिक कहना नही चाहता हूं और न उसका नाम लेना यहा पर उचित है । उस व्यक्ति को जिस जिस विकास क्षेत्र मे भेजा गया वहा उसने एन० ई० एस० ब्लाक की तरक्की करके उसे डेवलपमेंट ब्लाक मे बदलवा दिया । यह काम उसने केवल अपने परिश्रम से ही पूरा किया । हमारे यहा एक बडा कडा कमिश्नर था जो आसानी से किसी के सम्बन्ध मे रिपोर्ट लिखना नही जानता था, लेकिन उसने भी

[श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिह]

उसके बारे में यह लिखा कि : "The officer deserves accelerated pro· motion." फिर भी प्रोमोशन के वक्त उसी सिविल लिस्ट की चर्चा हुई और यह कहा गया कि उसका नाम बहुत पीछे है, इसलिये उसका प्रोमोशन नही होगा । मै समझता हूं कि ऐसा होने से परिश्रम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन नही मिलता है और उनकी लगनशीलता में वृद्धि होने के बदले कुछ कमी आती है । मैंने यह भी देखा है कि जो सरकारी कर्मचारी विकास क्षेत्र में काम करते हैं और जो नानआफिशल कार्यकर्ता उस इलाके में होते हैं, वहा उन दोनों में पारस्परिक सहयोग की भावना रही है, वहां काम कुछ अधिक हो पाया है और जहां एक दूसरे के प्रति खिचाव रहा है और जहा नानआफ़िशल उसमें काम करने वाले आफ़िशल को उसी दृष्टि से देखते रहे हैं जिस दृष्टि से वे पहले देखे जाते थे, वहां काम कम हो पाया है । मै समझता हूं कि चाहे फ़ैशनेबल लेडीज़ हों, या फ़ैशनेबल पुरुष हों, फैशन से कुछ बिगड़ता नही है । अगर किसी फ़ैशनेबल सोशल वर्कर में काम करने का माद्दा है तो वह काम करके अवश्य दिखला सकता है । लेकिन अगर उसके बदले आपने किसी भोंदू स्त्री को ले लिया और कहा कि यह बड़ी सीधी सादी औरत है, खादी पहनती है, गांव की बोली बोलती है पर वह जाकर इस लायक भी न साबित हो सकी कि वह स्त्रियों को योजना समझा सके तो उसका सीधापन, उसकी सादगी हमारे किस काम आयेगी ।

मैने जैसा शुरू में आपसे कहा, मै फिर उसको दोहराता हूं कि इसमें काम करने वाले पुरुष या काम करने वाली स्त्रियां जो भी हों, उनके चुनाव के समय एक ही बात का विचार होना चाहिये कि वे योजना माइन्डेड हैं या नही, योजना ने उनके हृदय को स्पर्श किया है या नहीं। उनमें योजना को अपनाने का माद्दा है या नहीं । मै समझता हूं कि साधारण बातचीत से, एक साधारण से इंटरव्यू से, अगर हम जानने की चेष्टा करें तो ऐसी बातें मालूम की जा सकती है । जो सब-डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किये जाते है अगर उनमें से कुछ लोगों को बगैर यह जाने बी० डी० ओ० या डेवलपमेंट आफ़िसर बनाया जाता है कि वे उससे दिलचस्पी रखते हैं या नहीं, तो उसमें हमको सफलता नहीं मिलेगी । आपका जो अप्वाइंटमेंट का ढंग है, वही रहे, लेकिन जो सब-डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर सिलेक्ट हो जाय, उनमें से आप जिनको इस काम में लगाना चाहें, उनके विचारों को जान कर, उनकी भाव भंगिमा को समझ कर कि उनके दिमाग में कोई आदर्श है या नही, उनका चुनाव करे । जिसको आप सामुदायिक विकास योजना में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खड के क्षेत्रों में काम करने के लिये भेजेंगे, अगर वे लगनशील व्यक्ति होंगे तो वे कुछ अर्से में उस काम को अच्छी तरह करने लगेंगे ।

श्री पा० ना० राजभोज : जो आदर्श काम करने वाले है, उनके खिलाफ़ हमने नही बोला है ।

श्री कृष्ण मोहन प्यारे सिह : मैंने बराबर इस बात की चेष्टा की है कि मै किसी माननीय सदस्य के वक्तव्य का खंडन न करूं, इसलिये मुझ पर गलत ढग का आरोप लगाने की आवश्यकता प्रतीत नही होती । मैने देखा है कि एक दो आदमी ऐसे भी है जिन्होंने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करके, और गाव वालों की भावना को समझ कर और उसकी इज्जत करके अधिक से अधिक काम किया है । मैने ऐसे भी लोग देखे है जो पढ़े लिखे सोशल आर्गेनाइज़र है और एम० ए०, बी० ए० और न जाने क्या क्या है, लेकिन अगर उनमें काम करने का माद्दा नही है तो उनकी योग्यता और उनकी डिग्री किसी काम की भी नही प्रमाणित हो पायी है ।

इन शब्दों के साथ ... ... फिर में आचार्य मल्कानी जी .. ... प्रस्ताव

हमारे सामने रख कर हमको यह अवसर दिया है कि जिस ंग से गांवों में काम हो रहा है और गांव गांव में जो काम करने वाले आदमी बिखरे हुये है उनक जा ुण है और साथ ही साथ उनमें जो खामियां हैं, और उनमें जो सुधार की आवश्यकता है, उनके प्रति सदस्यगण प्लानिंग मंत्री महोदय के सामने अपने भाव प्रकट कर सकें, उसके लिये बधाई देते हुये बैठता हूं ।

धन्यवाद ।

SHRI V. PRASAD RAO (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, I cannot subscribe to the scepticism expressed by some of the friends here and perhaps, the hon. Deputy Minister also might be thinking on those lines, that a Resolution of this sort will not be of much use, since it is vague, since it does not give any specific answer to the problem of eliciting the people's co-operation. I do not think that this Resolution will not be of use. If only to focus the attention on the necessity of enlisting the co-operation of people, if only to focus the attention of those bureaucrats who are in that state of stupor, who are in that state of elevation that these people are nothing and that they could carry on everything, if this Resolution is able to move such people, I think this will have more than served its purpose. So, Sir, I am not going to subscribe to the view that this Resolution by being discussed here will be useless.

I am not going into those factors, rather those basic policies, that are pursued by the Government, which are hampering the full measure of co-operation from the people. Take, for instance, the policy of taxation which, of course, unduly puts the weight of this development on the common man rather than on the richer classes. Of course, I am not going to give a dissertation over the taxation policies of the Government nor on those policies which do more favour to the bureaucrats or the landlords. I am not, on this occasion, going to pass a detailed criticism on those policies, but I shall refer only to those acts or things which are for the progress of all sections of the people. If such programmes are agreed to almost unanimously by all parties and by all sections of the people, why are we failing to elicit their co-operation even on such programmes and why has the Government failed to enlist the co-operation of all sections of the population? It is only on those things that I am going to dwell.

SHRI SONUSING DHANSING PATIL (Bombay): Question.

SHRI V. PRASAD RAO: Friends might question, of course. But they cannot question facts. They cannot question the practice. If the speeches that have been made here are any indication, it has become very clear that all the co-operation that could be got from the people is not being got. My friend may question from the other side, but facts remain as facts. Perhaps, if my friend had gone to the country-side and seen how much enthusiasm there is for some of the projects, for some of the Community Development projects, he could not have questioned like this; he could not have parried like this.

Anyway, take the question of Community Development where there is a lot of scope for eliciting the co-operation of the people. How much co-operation is being taken? I need not go very far to quote from the opposition sources, but the hon. Deputy Minister of Planning can go into the Community Projects evaluation reports. They themselves say that proper co-operation from the people is not forthcoming. Of course, the Minister might say, "What can we do? We have constituted committees. We have sought the people's co-operation in preparing such a big book as the Second Five-Year Plan. We are sending instructions, of course, to get all the parties' representatives and other people into these committees, and wherever it is possible, we are trying our best to get that co-operation. If people are not forthcoming, what are we to do? Do you mean to say that for everything

[Shri V. Prasad Rao.]

the Government is to blame? It has become the second nature of the Opposition to blame the Government for everything that is not being done." Perhaps in his whims our Deputy Minister might indulge in another peroration. But such an indulgence cannot be a substitute for a self-critical attitude which is so necessary to understand why exactly the people's co-operation is not forthcoming. Such an attitude, which, of course, the hon. Deputy Minister had displayed on a previous occasion, when we were discussing the land reforms, will not help even in future to get the co-operation of the masses that is necessary to carry our plans forward.

Sir, the first thing that I may point out as to why the necessary measure of co-operation is not forthcoming, as far as these community development projects are concerned, is this. I do not say that absolutely no co-operation is forthcoming. Certainly co-operation is forthcoming. There is no doubt about it. But the necessary amount of co-operation is not forthcoming because the necessary amount of enthusiasm is not generated among the people. If this simple thing is not understood and if this simple thing is forgotten in the midst of the verbiage of other reasons, then, of course, the basic thing cannot be understood, and even in future proper co-operation cannot be forthcoming. Suppose, for instance, there is a question of road-making. The people must be made to feel that their future is at stake and that it will be for their own betterment to have that development. It is only by making them realise and understand that it is necessary for their future progress in life that that particular road is necessary that we can get their whole-hearted co-operation. But unfortunately the administrative machinery which we have inherited from the Britishers is not the one that can very easily respond to the needs of our people or can get the necessary enthusiasm on the part of our people and their whole-hearted co-operation. Every one of us, Sir, understands perfectly well that the administrative machinery which we have inherited is not possibly the best-suited in the present age of development, in the present age of our welfare State, in the present age of getting the maximum co-operation from the people. In that case, taking into consideration the inadequacy of our administrative machinery and the prevalence of bureaucracy, it is the duty of the Government to see that people are associated with all phases of development and people are associated with such works. But association of our people does not mean cramming these committees with the people of their own faction and with the people of their own clique inside the Congress itself. I too have got the experience of these committees. I do not say that no committees are there in existence. In my own erstwhile State of Hyderabad or in the present State of Andhra Pradesh, of course, these block advisory committees have been formed, taluk development committees have been formed, district development committees have been formed. But may I know, Sir, by whom are these committees represented and who are the members of these committees? Are they representative of the people who are actually living there in that particular block or particular taluk or particular district?

SARDAR RAGHBIR SINGH PANJHAZARI (Punjab): Of course.

SHRI V. PRASAD RAO: Yes, I am presently coming to what sort of representation is that. If my hon. friend who says 'of course' thinks that defeated candidates in the elections represent the people there, then, of course, it is entirely a different thing. If by that my hon. friend means that those who forfeited the confidence of the people represent the people, of course, then they do represent, according to that concept, the people in that area. But if my hon. friend, the Deputy Planning Minister, goes into the thousands of complaints that are there in the erstwhile Hyderabad State from his own Congress organisation,

he will find that there were several complaints about the formation of those very committees. And he himself can understand how partially these committees were formed. Even the Bharat Sewak Samaj was made a pawn in the factional game inside the Congress itself. So, Sir, it may be very easy to say that people's co-operation is necessary and committees are there; these committees that are there, of course, might have genuinely been intended for the co-operation of the people, but actually they are being used to serve the interests of not even the Congress but of particular people inside the Congress in the name of people's co-operation. And naturally, if such things are going on, you cannot expect the people to come with open hands and co-operate with you. And then, Sir, if the block development officer or the block head goes into the village and stays with some local landlord there, he does not expect the co-operation of the agricultural labour who are naturally sceptical about the *bona fides* of the landlord for the development of the village. You do not expect ordinary agricultural labour to give its whole-hearted support to a block development officer or to such development officers who are apparently supporting those landlords. So also in the matter of co-operatives, you may be thinking that proper interest is not being taken by the masses. If 70 to 80 per cent. of the loans are going into the hands of those landlords, you cannot expect co-operation from any other sections of the peasantry. If co-operative societies are used as tools in the interest of usurpers in the village, you cannot expect co-operation from the other sections of the peasantry, and that is but natural. Unless these things are mended, there is no use saying that no co-operation is forthcoming from the masses. In this connection, Sir, I am reminded of the criticism made by my hon. friend who is not here, Mr. Chandulal Parikh. I know that he is very much allergic to communists But I do not blame him for that because he represents that class which is very much allergic to communists. Now, Sir, he alleged that under communism, under the powerful rule of the Communist Party, individual liberty is suppressed. I will tell him only one thing. Let him compare the present regime in Kerala where communists are in power with the previous 10 years' regime of the Congress inside Kerala, when section 144 was imposed and when no meetings were allowed for several years in Trivandrum. It is the Communist Government, it is the Communist Ministry that has for the first time lifted the ban on the meetings in Trivandrum. Does it mean that individual liberty and the individual freedom is suppressed by the Communist Party or by the Congress? It is for the first time that the Kerala Communist Ministry has invited friends from his own class, from the capitalist class, to frankly come and discuss matters that are to be adopted by the Kerala Ministry for the future development of Kerala. Does he mean to say that it is suppressing the individual liberty or individual freedom? If he means by individual freedom the freedom for the capitalists to suppress the working class with the help of the police, then certainly Kerala is not the place for him to choose. But if he means by that the development of industries with the public co-operation and with the help of the Government, then certainly, and with open arms, the Kerala Communist Ministry is inviting all the capitalists throughout India to come and invest there with the assurance that the Kerala Ministry is there to help and defend all the legitimate interests of the industrialists. So no importance need be attached to the insinuations that are levelled against the communists or the Communist party.

SHRI T. J. M. WILSON (Andhra Pradesh): May I interrupt?

SHRI V. PRASAD RAO: I am sorry I have no time. Otherwise, I would have welcomed interruptions. In fact, I would have been glad if you had given me a few more minutes and I would have certainly answered all

[Shri V. Prasad Rao.]

interruptions in that case; there is no doubt.

Coming to the question of co-operation, my friends might ask "What has your Government done? What has your Ministry done in Kerala to elicit co-operation?" May I remind those friends, of course many may be knowing but still may be pretending not to know it, and I may say for their benefit too, that immediately on the assumption of the Ministry, the Kerala Government did at every level have popular Committees with representatives of all sections of the people, including the Congress, not excluding any Party, unlike their practice in other States. For instance, in my own district, there are Block Advisory Committees where the communists had polled 80 per cent. of votes but still you don't find a single communist represented in that Committee. Such sort of practice has never been followed in Kerala but there every effort has been made, of course, to elicit the cooperation of other parties. Unfortunately, there today the Congress is mobilising the people not for any constructive programme, not for anything else but to invite repression. That is the method they are adopting and they say that at other places they are not able to get cooperation. Where you follow the right method or the right approach, certainly you can get the cooperation of the people but today by these wrong methods, by relying on landlords and capitalists, if you say that you are not getting that measure of cooperation which you should get, it is natural and it is inevitable. So besides formulating a correct policy, you must have a correct approach also to this matter. You must have faith in the masses so that you could mobilise the people.

I will cite one more example. You know Pandit Sundarlal who was a follower of Gandhiji. He had been to China and he said that half a million people could be gathered for the construction of Hoi river project and about which our own delegation had testified that such a gigantic project could be built in 80 days because of the cooperation of the people. It is high time we ponder why such co-operation is forthcoming there and not here. It is no use saying that it is because of the totalitarian Government or that this project could be built because the Government there compelled all the peasants and the masses to do so. Perhaps a totalitarian Government could get at the masses but they cannot make heroes of the people. A totalitarian Government, a dictatorship could never do that. It is only a Government that fulfilled the aspiration of the people that could do such things. So it is high time that our Government should analyse such things and see why such a cooperation is not forthcoming here. Certainly if China could do it, we can do it. I am fully confident that Indians could do it. I fully believe that we want to develop and if you want cooperation, you can get it provided the right approach is there. I, on behalf of my party, say that we are fully prepared to co-operate provided the Government is also prepared to cooperate.

THE DEPUTY MINISTER OF PLANNING (SHRI S. N. MISHRA): Mr. Vice-Chairman, it has been my privilege during this fortnight to attend to two Resolutions—I may say very important Resolutions—in this House, one following very closely the other. We are thankful to the hon. Members for exercising their minds on this very vital subject of public cooperation which I must mention is next to our heart as it must be to theirs. But it is my regret that so many points have been raised during the course of the discussion, ranging from family planning to anything that you can conceive of under the sun, that even if I move with a Sputnik speed, it would be difficult to keep pace with them.

I have listened to the debate with great interest and respect but I must confess that my sincere hope and

desire to be benefited by it has not been fulfilled. The tone was set by the hon. Mover of the Resolution, and along with him a number of other friends seemed to give me an impression as if they had retired to the Himalayas during the last five years of very vital developments in India. I would also mention this in this particular field of public cooperation. There is no doubt that it would do well if the hon. Members should always keep this subject under their review because they are very close to the people. But I am sorry to find that the debate on this Resolution has been sought to be converted into a general debate on the Plan—the Plan, its structure and philosophy; the Community Development Projects, their structure and philosophy; the dichotomy between public and private enterprises and things of that kind. For many things raised, I may submit that the proper time for taking them up would come when the Budget Debate commences or earlier when this House takes up, if there is such a motion as the consideration of the working of the Second Plan. So I would not like to throw any light on many of the points which have been raised. And if hon. Members feel somewhat disappointed, I can only say that I am helpless in view of not very strict relevance of those points to the discussion this afternoon.

Before I begin to take up some of the important points, I would like to thank my hon. friend Shri Algu Rai Shastri for his very emphatic and eloquent speech opposing this motion. I know that there are very few persons who can equal him in his eloquence and the effectiveness of the language which he has used.

After having said that, I would like to say at the very outset that we consider that public cooperation is the very breath of democratic planning and particularly in an under-developed country. It is my firm opinion that in an under-developed country we have not only to build an economy but to build a nation. I would like to explain this at some length. Without public cooperation you may build capital, you may even achieve the targets that you have laid down in the Plan but you would not be able to build the human beings. Those very targets that you achieve may lack the very vital throbbings of life, they may be dead targets, they may not be the symbols of life. So it is the considered opinion of the Government as it is no doubt of the hon. Members that we must do everything to secure public cooperation. But when the hon. Members were all the time directing their attention to the Government in this respect, I was feeling a little surprised because as representatives of the people, hon. Members should have brought some fresh experience and also told the House what they have been doing particularly in this field.

4 P.M.

We have here about 750 representatives of the people, not in this House only, but in both the Houses together. And we have about 4,000 representatives all over India, functioning in the legislatures. Sir, we have the Members of Parliament and those of the State legislatures functioning in the 328 District Development Committees all over the country. Members of Parliament and members of the legislatures again are functioning in the Block Advisory Committees which would be numbering about 5,000 throughout the country at the end of the Plan. These are very important and vital bodies in which the hon. Members have the scope for thinking out ways and means of securing public cooperation. But they have not said anything concrete as to what have been their experiences while working in these very important bodies. Sir, when I hear them saying that Government is doing or not doing something, in this field, I am reminded of what Bernard Shaw said in this Preface to the Apple Cart—"So you see, I cannot be a Christian except through the Gov-

[Shri S. N. Mishra.]

ernment's action." This seems to be the mentality which is gripping hon. Members. They are always thinking of the Government while they are thinking of public cooperation. It is quite clear, Sir, that any government would fall short of the requirements of the situation. Any Government is bound to prove small in relation to the great needs of the situation. Any party, be it the party to which I have the honour to belong, is bound to fall short of the requirements of the situation. So the whole nation has to gear itself up to the task.

Sir, some hon. Members at times feel somewhat sceptical and cynical about the targets which they seem to criticise as ambitious. I would like to say that if the whole nation puts forth its best, there should be absolutely no doubt that we shall not only achieve the targets, but we would be able to go much beyond them. We may not have any control over the foreign exchange resources. But the internal resources should not only be achieved but they can be multiplied manifold if all the representatives of the people put their shoulders to the wheel.

Sir, what are the important principles on which public cooperation may be expected to be achieved? some hon Members have tried to throw light on this question. An individual, when he feels that his interest is completely identified with the programme, can take part in the implementation of the programme. When he feels that he has some share in the forming of the decisions, then he can take part enthusiastically in the implementation of those decisions. Now, how was this Second Five Year Plan formulated? I am not here to go into all the details connected with that. These are well known to this House. Not only the legislatures, but a large number of public bodies all over the country were consulted during the formulation of the Second Five Year Plan. So we can say in a real sense that this is a people's plan. That being so, it is for the people's representatives to see that this people's plan is carried out by the people with all energy and enthusiasm. It is, of course, necessary for the Government to create conditions in which the public representatives and the people can put forth their best. I shall come presently to what the Government has been doing to create those conditions.

Sir, this Resolution wants to place before us, in an implied way, that nothing is being done, or that very small or scanty efforts are being made to secure public cooperation at all levels. What is exactly in the mind of the hon. Mover is not quite clear to me. Does he want committees at all levels to serve this purpose? If that is his intention, that has already been done. From the very base to the apex, we have now a continuous chain of these organisations. We have got the village panchayats which probably number about 123,000 all over the country. And then we have got, above the panchayats the Block Advisory Committees. Above them there are the District Advisory Committees and then at the State level there are the State Planning Advisory Committees. When you come to the national level, you have got the Consultative Committees of the Members of Parliament, both for Planning and for the Community Development Programme. You have got the National Advisory Committee on Public Cooperation. In the same way you have got the Bharat Sevak Samaj and other organisations working which Government has ben trying actively to assist. So in this way you have got an organisational set-up from the village panchayat up to the National Advisory Committee here. In all these committees it is the Members of Parliament and the members of the State legislatures and other leading

public representatives who have been functioning. Take for example these village panchayats, on which rightly on. Members have concentrated a good deal of attention. We attach a great deal of importance to the functioning of the village panchayats. Unless these small village republics function in an effective and vigorous manner, there is no salvation for the country. So we are laying a great deal of stress on these. The hon. Mover of the Resolution referred to the Balwantarai Mehta Committee Report in this connection and suggested something about democratic decentralisation. That is in fact the very core of the programme of the community development. It may be that by now we might not have succeeded to a great extent in setting up institutions, agencies and methods which might secure this end. But that is the very core of this programme. And as you must have observed during the course of discussion on this Resolution and earlier in this House, in this programme we lay a great deal of stress on the effective functioning of the village panchayats. Every village panchayat is entrusted with Rs. 2,000 which it can spend according to its programme. It is the village panchayats that formulate the programmes which have to be implemented in their areas, and it is with their active cooperation that the programmes are implemented. It may be, Sir, that there may be a snag here and there. It may be that there are deficiencies here and there. But they require some time, and I think the hon. Members' impatience in this respect may be justifiable on the basis of limited experience. But so far as the entire country is concerned, the village panchayats are going to be very actively assisted by the community development programme.

Another point that was generally mentioned was in connection with the difficulties in government offices and the hon. the Mover of the Resolution referred to red-tapism and the complex procedures which have generally been standing in the way of securing public cooperation. I very much sympathise with him and I agree to a certain extent that the procedures are complex in many cases and there are difficulties in Government offices. We are constantly giving thought to this aspect of the problem. But it has to be borne in mind that we have to create conditions in such a manner that there are no major upsets, leaving in the balance no good results. Anything that we do must not be of such a nature that there might not be the desired result. And, therefore, although we are giving very anxious thought to the reorganisation of administration and the simplification of procedures in the offices, it is sought to be done in a manner that there might not be a major upset.

Sir, I come from a State where, as you probably know, there have been some inspiring examples of public cooperation. The Mover of the Resolution was very kind enough to refer in very good words to the work being done on the Kosi Project and the Burhi Gandak Project. Sir, I am one of those who have had the privilege of working with thousands of young boys in NCC camps. I think at the time I visited the Kosi Project, about 9,000 to 10,000 boys were working on the Kosi Project. I lived with them for three days. I would never forget those three inspiring days that I lived with them

Again, Sir, in Burhi Gandak, Khion, Kamala and other embankments, you will be surprised to learn that about 550 to 600 miles of embankments had been constructed mainly with the cooperation of the village panchayats. My hon. friend over there was speaking something about Huoi Project in China which was completed with public co-operation within a very short time. Let us not slight what we have done in this country, what the people in this country have been doing. Here I give you an example that 550 to 600 miles of embankments were constructed during a short period of one

[Shri S. N. Mishra.]

and a half years. Just think of it, just think of the whole length of it; probably from Delhi up to Patna, the whole distance was covered by embankment with the active cooperation of the village panchayats in that area. Particularly in the present stage of lack of education, lack of training, this whole matter assumes great significance. Similarly, Sir, in the Kosi Project about which I mentioned. Not only the NCC boys worked there, not only the *shramdanis*, those people who give voluntary labour, worked there, but the Bharat Sevak Samaj organised the people on such a vast scale in labour cooperatives that it should excite the admiration of all. So, these are very important things that have been achieved with public cooperation.

Then, Sir, Prof. Thomas and some other friends mentioned something about the organisation of youth. Sir, casting a glance at me you can think how very enthusiastic I myself would be about the programme of the organisation of youth. I am associated with an organisation which has been sponsored by the Planning Commission and which is called the University Planning Forum. Some hon. members, particularly hon. Shri Deokinandan Narayan, spoke something about the Small Savings Campaign to be carried amongst the student population. This is an idea which we have already worked and, therefore, when I say that the hon. members seem to be absolutely innocent of some of the important things that we have been doing, I am not beside the mark. By this time, I would like to convey to the House, that the students and teachers in the Universities and the constituent colleges have been able to mobilise savings to the extent of Rs. 1,17,000. They inaugurated this programme only a few months back and they have been able to collect the amount. But the potentialities in this direction are much vaster and we are going to achieve them. This population of students and teachers in the Universities and the constituent colleges is going to bring about a revolution in the thinking of the people under the auspices of the University Planning Forum. It is a very vital movement of one million University men and women all over India. At the moment we have got a population of about 8 to 9 lakhs of students in the Universities and the constituent colleges. Probably they would go up to about 1·2 millions at the end of the Second Five Year Plan. So, let us look with hope to this vital movement of the University Planning Forum, which had done a good deal towards creating planning consciousness amongst the students' population and which had done vital work and thinking in respect of the Plan. Sir, what exactly is the idea behind the Planning Forums? Not only they have to create plan-consciousness amongst the University students and teachers but also amongst the boys and girls reading in high schools and other educational institutions. So, each Planning Forum has to take under its care about half a dozen high schools. If every college forum acts up to this, there should be about 2,000 schools benefiting under this scheme. So, it means that we have a programme of igniting not only one candle, but a chain of candles—these one million boys and girls spreading plan-consciousness amongst many million boys and girls in the high schools and teachers and boys and girls going to the countryside and spreading the message of the Plan.

I do not know whether I am nearing my time. I had 30 minutes but I think probably I have not spent more than 15 to 18 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. B. JOSHI): You have already finished 22 minutes.

SHRI S. N. MISHRA: I thought it was 18 minutes. So, I am sorry.

Sir, look at the contribution made by the people. Although it would

not be right to evaluate in terms of money what has been done by the people during the First Five Year Plan, on a most conservative estimate the contribution of the people in terms of money, materials and labour would come up to about Rs. 20 crores or so. I am told that under the Community Development Programme the contribution made by the people up-to-date is about Rs. 46 crores or so. Having said that, I would again advise the House not to look at the contribution made by the people in terms of money so much.

Now, Dr. Gour mentioned something about the constitution of a Project Committee. Sir, it is a good and concrete suggestion which came from him but I would like to inform the House here again that we have already taken steps so that in all important irrigation projects, there should be joint committees, consisting of the representatives of the administration and the public agencies engaged in securing public co-operation. We have already written to the State Governments and soon the results would be discernible. So we have already taken steps even in this respect.

SHRI V. PRASAD RAO: May I know if there is any such committee so far as the Nagarjun Sagar Project is concerned?

SHRI S. N. MISHRA: I have said that we have recently written to the State Governments about the constitution of such joint committees and they are soon going to be formed. In fact it is our idea that with all big projects the agencies concerned with publi co-operation should be associated.

Now, Sir, I would say a few words about the Sadhu Samaj, although the Government is not directly associated with it. This association has not come into being at the initiative of the Government. There seems to be a wrong impression in the minds of the hon. members of this House that this has been, in a sense, sponsored by the Government. This is a body which has been sponsored by the Bharat Sevak Samaj and we are glad that such a body has come into existence. It is no use making oblique remarks about the Sadhus. If they want to contribute to the development programmes, we should all welcome them. Their number is very vast and the number of their followers is vaster still. So, if we can bring them within the orbit of the construction programmes, it should be all to the good of the country.

Now, a few oblique remarks were made about the ladies associated with the Social Welfare Board activities. My hon. friend, Shrimati Savitry Devi Nigam, very effectively replied to them. I can only express my own regret over the remarks made about the ladies who are doing good work under the Social Welfare Board. Sir, I do think that the hon. member who made those remarks did not mean them, although the words seem to be creating that impression.

Now, Sir, some complaints were made by my hon. friend, Shri V. Prasad Rao. He said about some of the committees being filled with partisan men. I would strongly reject any such charge. Sir, if the hon. Member were to put down something in writing, we shall certainly enquire into it but I felt he perhaps was referring to past cases. If he has something to say about the constitution of certain committees, we shall certainly look into them and find out whether the accusations are correct.

SHRI V. PRASAD RAO: Plenty of things have been sent in writing.

SHRI S. N. MISHRA: There are many other points but as I told you in the very beginning, it would be difficult for me to cover all of them. I would say in the end, Sir, as you

[Shri S. N. Mishra.]

seem to be somewhat anxious about my finishing the speech now as you have to take up the other resolution, that in view of what I have said, this resolution would appear to you as reiterating what the Government is already doing and in connection with which Government has already done a lot and proposes to do a lot. It is not only in respect of social welfare programmes to which pointed attention seems to have been drawn in the resolution but all along the line we want to mobilise public co-operation—not only on the Government level, not only through the association of the public with the Government bodies but with the active co-operation of the public representatives and members of Parliament and of State Legislatures, the village panchayats, local bodies and all the rest of it. Sir, such resolutions seem to confuse more than help us because we do not know where we stand after doing all these things. If there are some concrete suggestions, they are all very welcome to us but concrete suggestions do not seem to have issued out of this debate. That is my regret and so the debate, in a sense, has been very disappointing and confusing. My hon. friend was saying that he could anticipate my speech. He tried to anticipate what was going to be my speech and he said that I was going to characterise this debate as a waste of time. Sir, I would be the last person to do that because after all, there are many useful points which have come out during the course of the debate which should receive the active consideration of the Government.

With these words, Sir, I would request the hon Mover of the Resolution to withdraw it. But before I do that, I would like to say again from the side of the Government that so far as we are concerned, we attach the greatest importance to securing public co-operation. I am reminded in this context of a Chinese saying. Probably this would please the hon. Members on the other side. The Chinese saying is that when the whole people sigh there is a storm and when the whole people bang their feet, there is an earthquake. Sir, with the whole people behind the Plan, there would be a real revolution which would transform society and transform people, their habits and their ways of thinking and I would invite the co-operation of all hon. Members in this direction.

Thank you.

SHRI N. R. MALKANI: Sir, my work has been made, to my mind, very light by the hon. Minister. Whatever he said was almost supporting what I said, with a little slant this side, with a slight tilt that side but in substance, I think, he sympathised almost with what I said. He said we are in need of public co-operation. We are in need of it; we all agree that public co-operation is necessary for the success of the Plan. We are all anxious to have it. The Reports say so; your Project Evaluation Report says so; your Vice-Chairman of the Planning Commission says so; the other day Dhebar Bhai said so. We have all said so with strength and great vehemence but, as far as public co-operation is concerned, it is not forthcoming as it should be. There is not that public enthusiasm which we desire or we want. The question is how to get it. My point is that these are the ways of getting it and I thought I had tried to give what are called concrete suggestions. It was not a vague thing. Everything that I mentioned was drawn from my experience. As a matter of fact, I drew on my experience fairly generously, experiences in Kashmir, Gujrat, Delhi, Bihar and so on. I would again reiterate that whatever I said was not theory. The hon. Minister knows very well that I speak from experience and all that I wanted was that what has been taken in hand should be pursued with the will, with the vigour, with the strength which I have not so far perceived. Perhaps that is the only difference between us. We want public co-operation; we do not see

public enthusiasm and we want to arouse public enthusiasm. I suggest this method and you suggest the very same method. We have just made a start but we have to make a very good start and give it a good push. I hope we will give it a good push. I do not want to press this Resolution for the reason I do not want to confuse either the Deputy Minister or the public or the Members of this House. If the Resolution confuses their mind, I would rather withdraw it. I do believe that the first Plan had a substantial success and I have been saying always that the first Plan had a substantial success. The second Plan is a good improved Plan; it is a plan for the people. I would not say that it is the people's plan. I wish it could be called the people's plan. It could be made the people's plan hereafter but today it is not the people's plan to my mind. At the same time, I do believe Government wants public co-operation and is anxious to have it. Before I withdraw the Resolution, I want to say to my friends here, Members of Parliament or of Legislatures in the States, that this is as much our duty as the duty of the Government. We get the Government we deserve and we deserve a better administration, a better policy, a more successful plan. We want the Government to be as responsible as we ourselves are. We cannot say we offer co-operation but it is not taken advantage of and in such a case we should not offer it. I am sorry to say that very few of us offer that co-operation which really sometimes Government solicits, at least the Community Projects Administration solicits and which it is not getting, I must say. The general public looks to us and we in turn look to the Government. It is a wrong and vicious circle. I would like to break that circle and say, not only Government, not only the administration but, in a sense, more than all that, we, Members ourselves who are in close contact with the public should say that our co-operation is forthcoming and that this is in turn will lead to public enthusiasm.

Sir, I do not wish to press this Resolution at all because there is not much of a difference between the Minister's point of view and my point of view.

*The Resolution was, by leave, withdrawn.

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION REGARDING BAN ON THE EXPORT OF MONKEYS

SHRIMATI RUKMINI DEVI ARUNDALE (Nominated): Sir, I move:

> *"This House is of opinion that* Government should ban forthwith the export of monkeys from India."

I am afraid, Sir, it is hardly worth while going through with this Resolution as there is really very little chance to put the case before the House or to get a reply from the Minister. Still I shall introduce the subject because I feel this is a vital question; it is something which affects the people of India as a whole and, since it is not possible for everyone to vote freely, as it is a moral issue, if it is at least possible for everyone to speak freely, I personally don't mind whether it is put to the vote or not.

It seems a strange thing that in this country it is so difficult to convince people on this particular question, a country which has for so long spoken about compassion and *ahimsa*. I cannot understand how there could be differences of opinion in regard to this export of monkeys when there is no doubt about the cruelty involved in it. First of all it brings tremendous suffering to millions of very sensitive creatures. We have no right to cause them so much suffering. They are supposed to be next to human beings in sensitiveness, and that is the reason why they are so much wanted by the laboratories. When they are so sensitive, it seems very strange that we are so insensitive to what they feel.

*For text of the Resolution, *vide* col. 1768 *supra*.